श्री नीरज डांगी: यह एलिगेशन वहां से आया है, इसलिए मैं अपनी बात को रख रहा हूं। ऐसे में, यह सोचना चाहिए कि जब मैं यहां बोल रहा हूं, तो मैं भी एक दलित वर्ग से आता हूं, मुझे भी बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। पता नहीं, मैंने ऐसा क्या कह दिया! ...(**व्यवधान**)... मैंने जो बात यहां रखी है, वह बात रखी है, तर्क के साथ रखी है, सत्यता के साथ रखी है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: प्लीज़, आप अपनी बात कहें।

श्री नीरज डांगी: इसलिए ऐसे में हम लोग चाहेंगे कि यहां जब आरक्षण की बात आ रही है, तो यह भी देखना चाहिए कि 50 फीसदी का जो गैप है, उसको भी कैसे हटाया जाना चाहिए, उसमें राज्यों को कैसे शामिल किया जाना चाहिए और यह देखना चाहिए कि 27 प्रतिशत और 22.50 प्रतिशत का जो मामला है, उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए। इन पर बात की जाए और इसको, जैसा कि मैंने निजी क्षेत्र की बात कही, उसमें भी इसका समायोजन होना चाहिए। मैं समझता हूं कि...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Please take your seat. Time is over. Hon. Members, as the time for Private Members' Legislative Business was till 4.30 p.m., we may now resume the General Discussion on the Union Budget. माननीय श्री गुलाम अली जी, आप बजट पर बोल रहे थे, बजट पर बोलने के लिए आपका जो समय बचा है, उसका उपयोग करें।

GENERAL DISCUSSION

#The Union Budget, 2024-25 - *Contd.*
&
#The Budget of Union Territory of Jammu & Kashmir, 2024-25 - *Contd.*

श्री गुलाम अली (नामनिर्देशित): डिप्टी चेयरमैन सर, शुक्रिया। आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया। भारत की वज़ीर-ए-ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण जी ने जो यूनियन बजट 2024-25 पेश किया और इसके साथ-साथ जम्मू-कश्मीर का जो बजट है, दोनों को लोक सभा और राज्य सभा में कंसिडरेशन के लिए रखा है, मैं उनके सपोर्ट में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जम्मू-कश्मीर में मोटे तौर पर बजट को enhance किया है और वहां जीडीपी बढ़ी है। सर, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही है कि जम्मू-कश्मीर की सवा करोड़ के करीब population है, लेकिन उसका जो employees का ratio है, वह बिहार जैसे बड़े स्टेट के बराबर है। इसके साथ ही वहां पुलिस के लिए स्पेशल

Discussed together.

असिस्टेंस पहली बार प्रोवाइड की गई है। डिप्टी चेयरमैन सर, जम्मू-कश्मीर में अमन लाना बहुत मुश्किल काम था, वहां कैलेंडर लगते थे और वहां गरीब के बच्चे पत्थर मारने के लिए इस्तेमाल होते थे। आज वहां गरीब का बच्चा स्कूल जाता है, आज ज़मीदार खेत में जाता है और आज वहां के लोगों ने - अभी जो रिसेंट इलेक्शन हुआ है, उसमें जो नेपोटिज्म था, जो फैमिली राज था, वह खत्म कर दिया है और वहां स्टोनपेल्टिंग निल हो गई है। मिलिटेंसी में लोकल लोगों की रिक्रूटमेंट कम हुई है, न के बराबर हुई है।

डिप्टी चेयरमैन सर, आज़ादी के बाद हमें इंडस्ट्री के लिए 14,000 करोड़ रूपये पिछले 60 सालों में रिसीव हुए, लेकिन अभी जो इन्वेस्टमेंट है, जो प्रपोज़ल है, वह 81 हज़ार, 122 करोड़ रुपए सिर्फ दो सालों में इंडस्ट्री के लिए वागुज़ार किए गए हैं, जिसके लिए 18,000 कनाल ज़मीन allot हो चुकी है।

वहां टूरिज्म दो तरह का होता है। जम्मू-कश्मीर की इकोनॉमी उस पर निर्भर है। पिछला जो डेटा है, वह 2 करोड़ के करीब हाईएस्ट है, जो भी हमारे देश में टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। इसके साथ ही कश्मीर को आज एक डेस्टिनेशन बनाया गया है, religious pilgrimage का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा है और जम्मू-कश्मीर अमन और खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। आज वहां स्ट्राइक के टेकर्स कोई नहीं हैं, कल तक जो बिजनेस वाला, रेहड़ी-पटरी वाला है, वह एक ख्वाब था, लेकिन आज वहां नरेन्द्र मोदी जी की रहनुमाई में, वज़ीर-ए-दाख़िला अमित शाह जी की रहनुमाई में और वहां एलजी प्रशासन के कारण गरीब आज अमन से अपनी नींद सोता है और रेहड़ी-पटरी वाला, छोटा बिजनेसमैन हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, वे अपने कारोबार पर जाते हैं। माननीय उपसभापति महोदय, हमने उन तबकों को - वहां जो सरकारें रही हैं, ज्यादातर कांग्रेस की सरकार रही है या वहां की रीजनल पार्टी, नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी की रही है, लेकिन हमारा ओबीसी समाज, जिसको ओएससी नाम की सिर्फ दो परसेंट रिज़र्वेशन थी...भारत सरकार ने नरेन्द्र मोदी जी की रहनुमाई में उनको बढ़ाकर 8 परसेंट किया है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बात करने पर विश्वास नहीं रखती, वह देने पर विश्वास रखती है। डिप्टी चेयरमैन सर, वहां शेड्यूल्ड ट्राइब्स को सिर्फ नौकरियों में और प्रोफेशनल कॉलेजेज में रिजर्वेशन थी। नरेन्द्र मोदी सरकार ने शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए वहां नौ सीटें रिजर्व की हैं। उसके साथ-साथ हमारा पीड़ित समाज ...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापति: आपका समय पूरा हुआ। आप जल्द खत्म करें।

श्री गुलाम अली: सर, प्लीज़, मेरी पार्टी का समय...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: यह पार्टी लिखकर देगी। आप अपनी बात खत्म करें।

श्री गुलाम अली: सर, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। इसके साथ-साथ वहां जो landless लोग थे, उनको पांच परले जमीन दी है। हमने लोगों जोड़ा है। कभी जम्मू और कश्मीर में लड़वाया है, कभी वहां के सेगमेंट्स हैं, गुर्जर और पहाड़ी में लड़वाया है। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, देश

के वजीर-ए-आज़म मोदी जी को, एचएम को मुबारकबाद दूंगा कि शफातरीन इलैक्शन हुआ है और जिसमें 60 परसेंट तक वोटिंग हुई है।

उपसभापति महोदय, 35 साल के बाद वहां election boycott नहीं हुआ है और आज इलेक्शन के प्रो में और लोगों में एक undercurrent है, जो लोगों का anti democratic expression था, आज pro democratic expression है। ...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापति: आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री गुलाम अली आज वहां सिनेमा फल-फूल रहे हैं। I am concluding, Sir. कश्मीर की कली, मेरे सनम, जब-जब फूल खिले जैसी फिल्मों की शूटिंग 1960-70 में हुई थी। आज वहां हमारे अजय देवगन जी की सिंघम, इमरान हाशमी की ग्राउंड जीरो और बड़े-बड़े जो मूवी वाले हैं, वे वहां शूटिंग कर रहे हैं।...(**व्यवधान**)... शुक्रिया।

श्री उपसभापति: गुलाम अली जी, आपका धन्यवाद। माननीय श्री विक्रमजीत सिंह साहनी। आपका पांच मिनट का समय है।

SHRI VIKRAMJIT SINGH SAHNEY (Punjab): Sir, I come from the State of Punjab which ensures India's food security for decades and ensures India's borders security since times immemorial.

"गुलिस्तां को लहू की जरूरत पड़ी
सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी
फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन
ये चमन है हमारा, तुम्हारा नहीं।"

महोदय, देश को जब-जब अन्न की आवश्यकता पड़ी, तो पहला अनाज पंजाब की धरती से आया। देश की सीमा पर जब-जब भी खतरा मंडराया, पहली शहादत पंजाब के जवान ने दी।

महोदय, बजट में कई राज्यों को विशेष ग्रांट्स दी गईं, यह बहुत अच्छी बात है। मैं फाइनेंस मिनिस्टर की सराहना करता हूं, लेकिन इसके साथ ही दुख भी प्रकट करता हूं कि पंजाब के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। पंजाब वह सूबा है, जिसने देश के बंटवारे का दर्द सहा, पंजाब वह सूबा है, जिसने उग्रवाद, टेररिज्म के मुश्किल दिन देखे, पंजाब वह सूबा है, जिसने अपनी छाती को छलनी करके अपना सारा पानी सुखाकर ग्रीन रेवोल्यूशन इस भारत को दिया, लेकिन आज वही पंजाब काफी मुश्किल में है। उस पर तीन लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है। मैं आपके थ्रू ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से दरख़्वास्त करता हूं कि जो बजटरी एलोकेशन 1.5 lakh crore किया गया है, जिसमें स्टेट्स को 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, Punjab should get a significant share. फाइनेंस मिनिस्टर ने 'GYAN' पर अपना बजट रखा - गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति। गरीब का जहां तक कन्सर्न है, बहुत अच्छी बात है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट को,

इस सदन को सोचना होगा, डिस्कस करना होगा कि कब तक हम फ्री राशन देंगे। Initiative सोचने होंगे कि कैसे हम उनको आत्मनिर्भर बनाएं और जो social inequality बढ़ रही है, top one per cent of India holds 42 per cent wealth. जहां तक अन्नदाता की बात है, total budget allocation of Rs.1.52 lakh crore agriculture sector के लिए किया गया। खासकर के जो pulses, oil seeds इम्पोर्ट हो रहे हैं, जो महंगे हो रहे हैं, it is a welcome step for crop diversification. However, some specific incentives and grants should be given. जो सात हजार रुपये पर एकड़ crop diversification का कृषि मंत्री जी ने आज किया, मैं समझता हूं कि वह कम है। वह कम से कम 15 हजार एकड़ होना चाहिए। जो किसान पहले जोहना, पैडी बो रहा था, अगर वह मिलेट्स पर शिफ्ट करता है...

सर, FPO की बात कही गई है। यह खुशी की बात है कि अब 10,000 FPO बनने जा रहे हैं, लेकिन Farmer Producer Organization (FPO) कैसे बनता है, उसमें 300 सदस्य चाहिए होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हैं, जैसे North East में 100 farmers should be okay. We should have a FPO. ज्यादा जरूरत है FPO से FPC की तरफ जाएं, क्योंकि cooperatives बनाना, FPO बनाना तभी फायदेमंद है, जब किसान को अपनी फसल का पूरा मूल्यांकन मिले। जो MSP बढ़ी है, जिसके बारे में आज सुबह कृषि मंत्री जी ने कहा है कि मैं किसान को भगवान मानता हूं,यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो इतना शोरगुल हुआ, उसमें केवल 10-20 seconds की बात थी, शोरगुल के बजाय उनसे यह पूछ लिया जाता कि समिति की कोई time limit कर दीजिए,उसकी रिपोर्ट कब तक आएगी, क्या वह 30 दिन में आएगी, 60 दिन में आएगी। जैसे ही समिति की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद उस पर चर्चा इस सदन में हो जाए, ताकि उसके बारे में पता लगे।

अगर हमने millets, jawar, bajra, ragi को promote करना है, तो इनको public distribution system में, mid-day meal में include करना होगा, तभी किसान उसकी फसल को बोयेगा। युवा के लिए जो 1.48 lakh crore रुपया skilling and education के लिए रखा गया है, यह बहुत अच्छी बात है। इससे 20 lakh youth skilled होंगे, 1,000 ITI upgrade होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जाती तौर पर 10 ITIs को पंजाब में Centre of Excellence बना रहे हैं। उसमें से तीन रेडी हैं। मैंने 5 World Skill Centres set करे हैं, जो बहुत अच्छे हैं। मेरा लक्ष्य पंजाब में 10,000 jobs create करना है। करीब 4,000 हमने क्रिएट किए हैं। बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा कि हम 1 crore youth को internship कराएंगे और 5,000 रुपए देंगे। मैं FM या Education Minister से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि skilling अपनी जगह पर है, लेकिन स्किल को हमें नौकरी के साथ जोड़ना होगा, skilling for jobs और private sector में internship के बाद कोई job security होनी चाहिए, क्योंकि KG से PG तक आम आदमी लाखों रुपए खर्च करता है, इसके बारे में आपको भी पता है। जो अग्निवीर योजना है, यह भी review होनी चाहिए। पता नहीं किसका यह brain child था कि 10 प्रतिशत चार साल के लिए कर दो, इसको हमें review करना चाहिए। ...(**समय की घंटी**) ... जो दूसरी armed forces हैं, उनमें उनके लिए कोई plan 'B' होना चाहिए कि हम चार साल बाद CRPF में जाएंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI VIKRAMJIT SINGH SAHNEY: Sir, I am concluding. वे BSF में जाएंगे या CISF में जाएंगे। हमें उनको कोई plan 'B' देना चाहिए। हम उनको इस तरह से खाली सड़क पर नहीं छोड़ सकते। हम सबको मिलकर इसका कोई समाधान ढूंढ़ना चाहिए। अगर कोई बजट की problem है तो इसको भी दूर करना चाहिए। Lastly, MSME के लिए, यह बहुत अच्छी बात है कि मुद्रा लोन को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया है, लेकिन मुद्रा लोन मिलता नहीं है, यह सिर्फ कागज पर है। मैंने पंजाब में देखा है कि वास्तविक रूप से जो बेरोजगार बच्चे हैं या जिन्होंने ।T। किया है, उनको बिना collateral के बैंक लोन नहीं दे रहे हैं। इसके बारे में survey होना चाहिए। यह जो credit guarantee scheme है, मुझे उम्मीद है कि stress period में ये banks खड़े रहेंगे। दो बातें हैं, 12 industrial park National Industrial Corridor Development Programme के तहत बनाए जाएंगे, मैं Finance Minister से दरख्वास्त करता हूं कि एक बड़ा industrial park लुधियाना या जालंधर में बनाया जाए और Food, fuel, fertilizer subsidy को कम न किया जाए, क्योंकि उसमें 26 परसेंट की कटौती है। सेमीकंडक्टर लैब के लिए 7,000 crore रखा है, लेकिन SCL, Mohali में यह already approve हो चुका है। मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको implement किया जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI VIKRAMJIT SINGH SAHNEY: Last, Sir, e-commerce जो export hub बन रहे हैं, यह MSME artisan बहुत अच्छी बात है। पंजाब में भी एक e-commerce export hub बनाया जाए। आखिर में, मैं कहना चाहता हूं-

"हो गई है पीर पर्वत-सी पिघलनी चाहिए,
इस हिमालय से, कोई गंगा निकलनी चाहिए।"
जय हिन्द।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Vikramjit Singh Sahney*ji*. Shri Dorjee Tshering Lepcha, maiden speech, not present. Shri G.C. Chandrashekhar, not present. Now, message from Lok Sabha.

MESSAGES FROM LOK SABHA

SECRETARY-GENERAL: Sir, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on Friday, 26th July, 2024, adopted the following motion:-